

प्रस्तावित भूमि का न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने किया निरीक्षण

जिला न्यायालय एवं बनेगा आवासीय परिसर, कार्य योजना तैयार करने के दिये गये निर्देश

नवभारत न्यूज
मऊगंज, 10 जुलाई, जिला न्यायालय एवं न्यायिक अधिकारियों के आवासीय परिसर के लिए आवंटित प्रस्तावित भूमि का न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा गतदिवस निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान भूमि की उपलब्धता, पहुँच मार्ग, आवश्यक आधारभूत सुविधाओं तथा भव्ी आवश्यकताओं के दृष्टिगत विभिन्न बिंदुओं का अवलोकन किया गया.

इस अवसर पर अधिकारियों ने न्यायालय भवन एवं आवासीय परिसर के लिए आवंटित भूमि की भौगोलिक स्थिति, सीमांकन, आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता तथा निर्माण कार्यों के



लिए आवश्यक व्यवस्थाओं का स्थल पर ही अवलोकन किया. साथ ही संबंधित विभागों के अधिकारियों को भूमि विकास एवं आवश्यक अधोसंरचना संबंधी कार्यों की समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए. अधिकारियों ने जिला

न्यायालय भवन एवं न्यायिक अधिकारियों के आवासीय परिसर के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि का स्थल निरीक्षण कर उपलब्ध सुविधाओं, भूमि की उपयुक्तता एवं विकास की संभावनाओं का अवलोकन किया. इस दौरान संबंधित

अधिकारियों को भूमि संबंधी आवश्यक अभिलेखीय एवं प्रक्रियात्मक कार्य समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए. संयुक्त निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने कहा कि जिला न्यायालय एवं आवासीय परिसर के निर्माण से जिले की न्यायिक

अधोसंरचना सुदृढ़ होगी तथा न्यायिक सेवाओं के संचालन में और अधिक सुविधा एवं प्रभावशीलता आएगी. जिला बनने के बाद से ही न्यायालय भवन एवं आवासीय परिसर की मांग उठ रही थी.

निरीक्षण में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा राकेश मोहन प्रधान, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय सिंह सरते, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक बुखारिया, कलेक्टर संजय कुमार जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट महादेव पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट ओ.सी. जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट आकांक्षा टेकाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट निसिता श्रीवास्तव तथा एसडीम मऊगंज एपी द्विवेदी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे.

अनुसूचित जाति विशेष परियोजना के प्रस्ताव होंगे तैयार

रीवा, 10 जुलाई, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति विन्ध्य एवं विकास निगम द्वारा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना लागू की गई है. इसके तहत अनुसूचित जाति वर्ग के सदस्यों के लिए वित्त पोषण संबंधी प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे. कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने इस संबंध में बताया है कि अनुसूचित जाति वर्ग के सदस्यों को लाभ देने के लिए कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, मछली पालन विभाग, उद्यानिकी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, ऊर्जा विभाग, कौशल उत्पन्न विभाग, आयुष विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा अन्य विभागों के अधिकारी कार्ययोजना तैयार करें. कार्ययोजना के प्रस्तावों को जिला स्तरीय समिति के अनुमोदित करारकर प्रस्तुत करें.



गुढ़ बस स्टैंड में कार और मोटर साइकिल की टक्कर बड़ा हादसा टला

नवभारत न्यूज
गुढ़, 10 जुलाई, शुक्रवार की दोपहर लगभग 3 बजे गुढ़ बस स्टैंड क्षेत्र में एक ईको कार और मोटर साइकिल के बीच टक्कर हो गई. प्राप्त जानकारी के अनुसार मोटर साइकिल पर एक युवक चालक सवार था, जिसे हल्की चोटें आई हैं. घटना में किसी प्रकार की गंभीर जनहानि नहीं हुई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया.

स्थानीय लोगों का कहना है कि गुढ़ बस स्टैंड क्षेत्र में सड़क किनारे एवं सड़क पर ही सब्जी और अन्य ठेले लगाए जाने के कारण वाहनों के आवागमन में लगातार बाधा उत्पन्न होती है. बसों, कारों और दोपहिया वाहनों को निकलने में परेशानी का

सामना करना पड़ता है, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है. गौरतलब है कि इस समस्या को लेकर कई बार सोशल मीडिया और समाचार माध्यमों के जरिए प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया गया है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है. स्थानीय नागरिकों ने मांग की है कि गुढ़ बस स्टैंड एवं नेशनल हाईवे-75 को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, ताकि भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके. नागरिकों का कहना है कि यदि समय रहते उचित व्यवस्था नहीं की गई तो आने वाले दिनों में और भी बड़े हादसे हो सकते हैं. जिसमें जान भी जा सकती है.

हाथियों के आतंक पर विधायक नागेंद्र सिंह सख्त

नवभारत न्यूज
गुढ़, 10 जुलाई, गुढ़ विधानसभा क्षेत्र के वनवर्ती गांवों में जंगली हाथियों के लगातार बढ़ते आतंक को लेकर विधायक नागेंद्र सिंह ने एक बार फिर वन विभाग पर कार्रवाई तेज करने का दबाव बनाया है.

उन्होंने प्रमुख सचिव, वन विभाग तथा वनमंडलाधिकारी, रीवा को अलग-अलग स्मरण पत्र भेजकर हाथियों से प्रभावित ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, क्षति का तत्काल सर्वे कराने और नियमानुसार शीघ्र मुआवजा दिलाने की मांग की है. विधायक ने बताया कि उन्होंने 7 जून 2026 को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर करियाझर, केरहा, इटार पहाड़, तमरादेश, टीकर सहित अन्य वनवर्ती गांवों में फरवरी 2026 से जंगली हाथियों द्वारा किए जा रहे उत्पत की

जानकारी दी थी. इसके बाद प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) कार्यालय ने 22 जून 2026 को सामान्य वनमंडल रीवा के वनमंडलाधिकारी को तीन कार्य दिवस के भीतर जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने तथा आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए थे. विधायक ने कहा कि विभागीय निर्देश जारी होने के बावजूद धरातल पर प्रभावी कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही है. हाल ही में ग्राम टीकर में हाथियों के दल ने दोबारा भारी उत्पात मचाते हुए कई कच्चे-पक्के मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया और किसानों की फसलों को रौंद दिया. इससे ग्रामीणों में भय और असुरक्षा का वातावरण बना हुआ है. नागेंद्र सिंह ने प्रमुख सचिव, वन विभाग से मांग की है कि प्रभावित क्षेत्रों में वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम तैनात करे.

बकायादारों से वसूली के लिए परिषद करेगी कठोर कार्यवाही

नवभारत न्यूज
चाकघाट, 10 जुलाई, नगर परिषद चाकघाट के वार्डों में निवासरत बकाया दरों के विरुद्ध अब परिषद कठोर कार्यवाही करने की तैयारी कर ली है.

नगर परिषद के निवासियों से संपत्तिकर, समकेतिक कर,

जलकर एवं अन्य सभी प्रकार की बकाया राशि वसूली हेतु पूर्व में नगर परिषद कार्यालय द्वारा कई बार नोटिस एवं सार्वजनिक सूचना दी जा चुकी है, उसके बावजूद भी कई लोगों के द्वारा कई वर्षों से बकाया राशि जमा नहीं किया जा रहा है. निकाय की

बकाया राशि वसूली हेतु अब परिषद न्यायालयीन कार्यवाही करने जा रही है. नगर परिषद के मुख्य नगरपालिका अधिकारी शंखधर पांडे ने चर्चा के दौरान बताया है कि नगर परिषद क्षेत्र के कई ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर कई वर्षों से निकाय की राशि बाकी है

किंतु उनके द्वारा राशि जमा नहीं की जा रही है. शंकरधर पांडे ने निकाय के बकायादारों से आग्रह किया है की वे परिषद की संपूर्ण बकाया राशि शीघ्र जमा कर दें अन्यथा उनकी विरुद्ध न्यायालयीन कार्यवाही की जाएगी.

शुरुआती बारिश में ही खुली नगर परिषद के दावों की पोल

नवभारत न्यूज
गुढ़, 10 जुलाई, जिले के गुढ़ नगर परिषद के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 6 और वार्ड क्रमांक 8 को आपस में जोड़ने वाली मुख्य गली इस समय बदहाली के आसू बहा रही है.

मानसून की शुरुआती बारिश ने ही नगर परिषद के विकास के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी है. वर्तमान में इस गली की हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि पूरी सड़क पर घुटनों तक गंदा



पानी और कीचड़ जमा हो गया है

जिससे यह मार्ग पूरी तरह से एक

तालाब के रूप में तब्दील हो चुका है.

इस मार्ग से प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में स्कूली बच्चे और स्थानीय नागरिक आवागमन करते हैं. वर्तमान स्थिति यह है कि छोटे-छोटे बच्चों को इसी गंदे पानी और कीचड़ के बीच से होकर स्कूल जाना पड़ रहा है. कई बार बच्चे इस फिसलन भरे रास्ते पर गिरकर चोटिल भी हो रहे हैं और उनकी किताबें व स्कूल बैग खराब हो रही हैं. इसके अलावा

स्थानांतरण के बाद भी पूर्व सचिव वर्तमान को नहीं दे रहे हैं प्रभार

नवभारत न्यूज
चाकघाट, 10 जुलाई, त्योंथर जनपद क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में स्थानांतरण के बावजूद ग्राम पंचायत के सचिवों द्वारा नए सचिवों को प्रभार नहीं दिए जाने के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं.

स्थानांतरण एवं निलंबन के बाद दूसरी जगह पहुँच जाते हैं और कार्यमुक्त हुए पंचायतों का प्रभार नए सचिव को नहीं देते.

ऐसा ही एक मामला ग्राम पंचायत चौखड़ा का सामने आया है जहां पर पूर्व पंचायत सचिव ग्राम पंचायत चौखड़ा अरविन्द सिंह अतिरिक्त प्रभार में थे. रिक्त ग्राम पंचायत चौखड़ा में सचिव निरंकार सिंह को ग्राम पंचायत चौखड़ा में पदस्थ किया गया है. अरविन्द सिंह की मूल ग्राम पंचायत सूती है जहां पर वो वर्तमान में पदस्थ हैं किंतु प्रभार की ग्राम पंचायत चौखड़ा का

अभिलेख नए सचिव निरंकार सिंह को नहीं दे रहे हैं. इस संदर्भ में चौखड़ा ग्राम पंचायत में नवपदस्थ सचिव निरंकार सिंह ने जनपद त्योंथर के मुख्य कार्य पालन अधिकारी को पत्र लिखकर आग्रह किया गया कि चौखड़ा का प्रभार पूर्व सचिव अरविंद सिंह से दिलाया जाय. जिससे प्रशासनिक जानकारी एवं पंचायत संबंधी जानकारी उच्च अधिकारियों को समय रहते भेज

जा सके. आश्चर्य है कि स्थानांतरण के बावजूद भी सचिव अरविंद सिंह द्वारा चोपड़ा पंचायत के सचिव पद का प्रभार एवं आवश्यक दस्तावेज नए सचिव को नहीं दिया जा रहा है. इस संदर्भ में त्योंथर जनपद के मुख्य कार्यालयन अधिकारी प्रवीड वंशोड ने बताया कि सचिव अरविंद सिंह से प्रभार देने के लिए कहा गया है. नहीं तो कार्यवाही की जाएगी.

जनपद अध्यक्ष ममता तिवारी के निरीक्षण में कृषि विभाग की बदहाल व्यवस्था उजागर

नवभारत न्यूज
नईगढ़ी, 10 जुलाई, खरीफ सीजन के बीच किसानों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनपद पंचायत नईगढ़ी की अध्यक्ष ममता कुंज बिहारी तिवारी ने कृषि विभाग नईगढ़ी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान विभाग की कार्यप्रणाली के साथ-साथ कार्यालय की मूलभूत व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया गया. इस दौरान कई ऐसी कमियां सामने आई, जिन्होंने विभागीय व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए. निरीक्षण में सबसे बड़ी कमी यह सामने आई कि कृषि विभाग कार्यालय में पीने के स्वच्छ पानी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है. इतना ही नहीं, कार्यालय में पदस्थ महिला कर्मचारियों के लिए



शौचालय की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं मिली, जबकि यहां अधिकांश कर्मचारी महिलाएँ हैं. ऐसे में महिला कर्मचारियों को रोजमर्रा के कार्य के दौरान असुविधा का सामना करना पड़ता है. निरीक्षण के दौरान मौजूद लोगों ने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए विभिन्न

योजनाएं संचालित करने तथा 'लाड़ली बहना योजना' जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं का व्यापक प्रचार करती है. लेकिन दूसरी ओर सरकारी कार्यालयों में महिला कर्मचारियों के लिए शौचालय जैसी बुनियादी सुविधा का अभाव इन दावों पर सवाल खड़ा करता है. उनका कहना था कि जब सरकारी कार्यालयों में

ही महिलाओं की मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी होगी, तो महिला हितैषी दावों की सार्थकता पर प्रश्न उठाना स्वाभाविक है. जनपद अध्यक्ष ममता कुंज बिहारी तिवारी ने कार्यालय की व्यवस्थाओं पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों से पेयजल, शौचालय एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं तत्काल

उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. साथ ही चौकीदार के लॉबित वेतन के संबंध में भी आवश्यक कार्रवाई कर शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने को कहा. निरीक्षण के दौरान विभागीय कर्मचारियों से किसानों को खाद, बीज, अनुदान एवं अन्य कृषि सुविधाओं का समय पर लाभ दिलाने के संबंध में भी चर्चा की गई.

चौकीदार ने अध्यक्ष के सामने रखी अपनी पीड़ा

निरीक्षण के दौरान कार्यालय के चौकीदार कमाल अहमद ने भी अपनी पीड़ा जनपद अध्यक्ष के सामने रखी. उन्होंने बताया कि उन्हें पिछले 14 महीनों से वेतन नहीं मिला है. इसके अलावा अन्य अव्यवस्था मिली. कृषि विभाग कार्यालय में सामने आई इन कमियों के बाद अब यह देखना होगा कि विभाग इन समस्याओं का समाधान कितीनी जल्दी करता है और महिला कर्मचारियों व कर्मचारियों की बुनियादी सुविधाओं के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं.

शिक्षा विभाग बच्चों के शैक्षणिक स्तर को सुधारते हुए उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम दें : शीलेन्द्र

कमिश्नर ने विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश

नवभारत न्यूज
रीवा, 10 जुलाई, स्वास्थ्य विभाग के सभी चिकित्सक एवं कर्मचारी जिलों में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दें, किसी भी स्थिति में गर्भवती महिलाओं की जान को खतरे में डालते हुए घर में प्रसव न कराया जाए, प्रसव हर हाल में अस्पताल में हो. स्वास्थ्य विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के कर्मचारी लगातार फील्ड में भ्रमण करें. उक्त निर्देश रीवा संभाग के

कमिश्नर शीलेंद्र सिंह ने महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ऊर्जा विभाग, जनजातीय कार्य विभाग, जल संसाधन विभाग, पीएचई, जल निगम विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग की बैठक में दिए. कमिश्नर ने एएनसी रजिस्ट्रेशन की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की और निर्देश दिए कि किसी भी जिले में एएनसी रजिस्ट्रेशन 95 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए. इसके लिए उन्होंने स्वास्थ्य विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग के कर्मचारियों को सभी गर्भवती महिलाओं का चिन्हांकन कर उनकी प्रथम माह से



9 माह तक नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच कराने के निर्देश दिए.

गर्भवती महिला यदि एनिमिक है या सीवियर एनिमिक है तो तत्काल उन्हें उच्च स्तर की

स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाए.

कमिश्नर ने कहा कि गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण दूर करना स्वास्थ्य विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग की

महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, कमिश्नर ने रीवा जिले में स्वास्थ्य के हर पैरामीटर पर किए गए गुणवत्ताविहीन कार्य पर सख्त नाराजगी व्यक्त की और कहा कि ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर

यदि कर्मचारी कार्य ठीक से नहीं करेंगे तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. कमिश्नर ने स्कूल शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्कूली बच्चों के शैक्षणिक एवं मानसिक स्तर में व्यापक सुधार करें, कक्षा आठवीं तक के बच्चों को लिखना, पढ़ना, जोड़, घटाना और गिनती अनिवार्य रूप से आनी चाहिए. कमिश्नर ने आगामी 15 दिवस में पाठ्य पुस्तक एवं साइकिल वितरण का कार्य पूरा करने के निर्देश दिए और कहा कि सभी बच्चों की अपार आईडी प्राथमिकता से बनाई जाए.

विद्युतीकरण का कार्य समय सीमा में पूरा करें

ऊर्जा विभाग की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने निर्देश दिए की ऊर्जा विभाग के अधिकारी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें. उन्होंने घरती आबा कार्यक्रम के अंतर्गत विद्युत से संबंधित सभी कार्य समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए और कहा कि जहां ट्रांसफार्मर खराब हो चुके हैं उन्हें प्राथमिकता से सुधारा जाए और जहां जहां ट्रांसफार्मर की मांग है वहां पर प्राथमिकता से ट्रांसफार्मर स्थापित किये जाए. कमिश्नर ने शहरी क्षेत्र में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर के कार्य की प्रगति की समीक्षा की और निर्देश दिए की मजरा-टोलों में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण का कार्य समय सीमा में पूरा कर लिया जाए. जल संसाधन विभाग की समीक्षा के दौरान कमिश्नर ने गंगा कछार अंतर्गत निर्माणाधीन योजनाओं की जानकारी ली और निर्देश दिए कि रबी सीजन में खेतों को पानी मिले. इसके लिए अभी से कार्य शुरू करना बना ली जाए. नर्मदा घाटी विकास विभाग की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने नागोद-सतना शाखा नहर, भू अर्जन में कार्यवाही और रीवा शाखा नहर की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की.